यूनिट 2 :: पंचवर्षीय योजनाएं और भारत में पर्यटन का विका

1. संरचना

2. उद्येश्य

2.1 परिचय

2.2 पर्यटन योजनाओं के निर्माण की प्रासंगिकता

2.2.1 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पर्यटन के विकास को समझने की कोशिश

2.3 प्रथम द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनायें तथा वार्षिक योजनायें ।

2.3.1 प्रथम पंचवर्षीय प्लान (1951-56)

2.3.2 द्वितीय पंचवर्षीय प्लान (1956-61)

2.3.3 तृतीय पंचवर्षीय प्लान (1961-66)

2.3.4 वार्षिक प्लान (1966-69)

2.4 चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पंचवर्षीय प्लान

2.4.1 चौथा पंचवर्षीय प्लान (1969-74)

2•4•2 पांचवां पंचवर्षीय प्लान(1974-79)

2•4•3 छठवां पंचवर्षीय प्लान(1980-85)

2.4.4 सातवां पंचवर्षीय प्लान(1985-90)

2.5 आठवां,नौवां और दसवां पंचवर्षीय प्लान

2.5.1 आठवां पंचवर्षीय प्लान (1992-97)

2.5.2 नौवां पंचवर्षीय प्लान (1997-2002)

2.5.3 दसवां पंचवर्षीय प्लान (2002-2007)

2.6 ग्यारवां और बारवां पंचवर्षीय प्लान

2.6.1 ग्यारहवां पंचवर्षीय प्लान (2007-2012)

2.6.2 बारहवां पंचवर्षीय प्लान (2012-2017)

2.7 समापन

2.8 मुख्य शब्द

2.9 प्रगति जांचने के लिए कुछ संकेत

2.10 फिर पढें

2. उद्येश्य

इस यूनिट को पढ लेने के बाद आप -

• पंचवर्षीय योजना की अवधारणा और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना सीख जायेंगे।

• पर्यटन के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उठाये गये प्रमुख कदमों से परिचित हो जायेंगे।

2.1 परिचय

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा (यूनिट -18,बी टी एम सी -133) से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। आप को पता है कि 1947 में आजादी मिलेने के बाद, भारत सरकार नें एक केन्द्रीकृत समन्वित योजना का प्रारूप तैयार किया था। इसमें हर योजना के क्रियान्वयन के लिए पांच वर्ष का समय निर्धारित होता था इसलिए इसे 'पंचवर्षीय योजना' के नाम से जाना जाता है। योजनाओं की परिकल्पना, कार्यान्वयन और देखरेख का काम योजना आयोग (बदलते भारत में इसे भंग कर के 'नीति आयोग' नाम से एक नया प्लानिंग कमीशन गठित कर दिया गया है।) द्वारा किया जाता था। 'नीति आयोग' के गठन से पहले, सन 1951 और 2017 के बीच, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया गया।

अपनी अबतक की समझ को आगे बढाने के लिए, इस इकाई में हम, इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में , पर्यटन के विकास के लिये, प्रत्येक योजना में किये गये प्रावधानों और महत्वपूर्ण कामों को समझने का प्रयास करेंगे । लेकिन इससे पहले हम, किसी पर्यटन-स्थल के विकास के घटक के तौर पर 'पर्यटन-योजना' की अहमियत को समझने का प्रयास करेंगे।

2.2 पर्यटन योजना तैयार करने का औचित्य

आजादी के समय हमारा देश बहुत गरीब था। किसानों तथा कारीगरों के शोषण, कृषि उत्पादों और औद्योगिक विकास में कमी जैसी सामाजिक आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था । कह सकते हैं कि भारत को अपनी अर्थव्यव्स्था का निर्माण बिलकुल शून्य से शुरू करना था। अत: देश में उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए, उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा कर के, जनता का जीवन स्तर सुधारने के उद्येश्य से, 15 मार्च सन 1950 को 'योजना आयोग' का गठन किया गया। देश के सभी संसाधनों का आकलन करने, कमी वाले संसाधनों को बढ़ाने और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए उनके प्रभावी उपयोग की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी 'योजना आयोग' को दी गयी। इसलिए, 'योजना आयोग' ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जो तत्कालीन यूएसएसआर में प्रचलित विकास के माडल के आधार पर तैयार किये गये केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम होते थे।

भारत को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा चूंकि अनाज के आयात पर खर्च करना पडता था, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कृषि उत्पादन बढाने के लिए सबसे पहले, सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण सन 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा

सकी । सूखा और तनाव के सम्मिलित प्रभाव में भारतीय मुद्रा की कीमत गिरती गयी और फलस्वरूप महंगाई बढ गयी । संसाधनों के क्षरण के चलते भी योजना बनाने की प्रक्रिया बाधित हुई। 1966 और 69 के बीच के तीन वर्षो को तीन वार्षिक प्लान मान लिया गया । केन्द्र में राजनीतिक संकट के कारण पहले 1978 में और उसके बाद 1990 में भी पंचवर्षीय योजना दो दो वर्ष के लिए बाधित हुई।

2.2.1 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पर्यटन विकास को समझने का प्रयास

पर्यटन उद्योग से रोजगार का सृजन, विदेशी मुद्रा की कमाई और बुनियादी ढांचे का विस्तार होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और पर्यटक तथा स्वागती देश के बीच सांसकृतिक सौहार्द स्थापित होता है। पर्यटन एक पूंजीप्रधान उद्योग है। यह होटल, रिसॉर्ट, रेस्तरां, सिनेमाघर,शापिंग माल,यातायात की सुविधाओं -- जैसे उडडयन केन्द्रों,सडकों,जलयानों और रेलवे सहित कई-तरह से उपयोग में आने वाले बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन योजना बनाने में पर्यटन केन्द्रों के समुचित विकास,रख-रखाव और प्रचार का बडा महत्व होता है। योजना को साकार करने के लिए आयोग को अपने बजट में आवश्यक धन का प्रावधान करना पडता है। पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ लक्ष्य तय किये जाते हैं जिन्हें निर्धारित अवधि में पूरा करना होता है। बजट आवंटन के साथ, योजना आयोग द्वारा, नई और मौजूदा परियोजनाओं, योजनाओं और रणनीतियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। पांच साल की निर्दिष्ट समयावधि में

अधिकारियों को, संबंधित योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों और रणनीतियों को लागू करना होता है।

पंचवर्षीय योजना बनाते समय,पर्यटन उद्ययोग से सम्न्धित जिन कार्यक्रमों और रणनीतियों को शामिल किया जाता है ,मोटे तौर पर वे निम्नवत हैं-

- पर्यटन से जुडी अधिरचनायें जैसे - होटल, एयर लाइंस,एयर पोर्ट ,रेलवे , पर्यटन रेलगाडियों,क्रूज का विकास करना ।
- पर्यटन केन्द्रों का आकर्षण बनाये रखना। यात्रा परिपथों को विकसित और सुसज्ज्ित करना ।
- मानवसंसाधन का सृजन तथा सेवा प्रदाताओं की क्षमता का विस्तार करना ।
- पर्यटन की नीतियां, और पर्यटन केन्द्रों से सम्बन्धित योजनायें।
- वाह्य तथा आंतरिक विपणन ।
- अनुसंधान और विकास ।
- सतत विकास।
- सामाजिक सहभागिता ।
- पर्यटन विकास में सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं की भागीदारी।
- पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन और रियायतें ।
- उत्तोलन प्रौद्योगिकी ।
- राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय। टेबुल 2.1 भारत की
- पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन विकास के लिए बजट आबंटन

पंचवर्षीय प्लान	प्लान की अवधि	योजना आबंटन(रूपये में)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-56	00
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-1961	336.38 लाख
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-1961	336.38 लाख
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961-1966	800 लाख
भारत पाक युद्ध तथा अकाल के कारण तीन वार्षिक योजना	1966-67	58.50 लाख
	1967-1968	87.65 लाख
	1968-69	183.81 लाख
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969-74	36 करोड
पंचम पंचवर्षीय योजना	1974-79	133 करोड
केन्द्र में राजनीतिक उथल पुथल के कारण रोलिंग योजना	1978-80	
छठी पंचवर्षीय योजना	1980-85	187.46 करोड

सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-90	326.16 करोड
राजनीतिक उथल पुथल के कारण वार्षिक योजना	1990-91	83 करोड
	1991-92	90 करोड
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992-97	773.62 करोड
नवीं पंचवर्षीय योजना	1997-2002	793.75 करोड
दसवीं पंच वर्षीय योजना	2002-2007	2900 करोड
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना	2007-2012	5156 करोड
बारहवीं पंचवर्षीय योजना	2012- 2017	16000 करोड

अपनी प्रगति की जांच करें - 1

1) पंचवर्षीय योजना से क्या तात्पर्य है । भारत में इसे क्यों लाया गया ।

.....

.....

2) पर्यटन में पंचर्षीय योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालिये ।

.....

.....

2.3 प्रथम द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनायें और वार्षिक योजनायें

इस भाग में हम पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं और तीन वार्षिक योजनाओं में पर्यटन के विकास के लिए किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालेंगें।

2 .3.1 प्रथम पंचवषीय योजना - 1951-56

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में पर्यटन को शामिल नहीं किया गया था। आज की तुलना में उस समय की प्राथमिकतायें बिलकुल ही अलग हुआ करती थीं। उस जमाने में पर्र्यटन का स्वतंत्र मंत्रालय भी नहीं होता था । पर्यटन को सन 1949 में यातायात मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग विभाग के रूप में शामिल किया गया । बजट आबंटन यातायात मंत्रालय के लिए किया जाता था जिसमें

पर्यटन के विकास के लिए खर्च भी शामिल रहता था । प्रथम पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए किये गये प्रावधान में प्रचार सामग्रियों तथा देश विदेश में पर्यटन कार्यालयों की स्थापना का खर्च भी शामिल रहता था । प्रथम पंचवर्षीय योजना में पर्यटन से सम्बन्धित सबसे खास काम यह हुआ कि पर्यटन, जो यातायात मंत्रालय के अंतर्गत टूरिस्ट ट्रैफिक शाखा के रूप में स्थापित था , 1955-56 में उच्चीकृत करके उसे टूरिस्ट ट्रैफिक विभाग बना दिया गया । इस उचचीकरण के फलस्वरूप जुलाई 1955 मे लंदन में,फरवरी 1956 में पेरिस में, सितमबर 1956 में मेलबौर्न में और 1956 के अक्तूबर में भारत का टूरिस्ट कार्यालय स्थापित करना सम्भव हुआ ।

2.3.2 द्वितीय पंचवषीय योजना - 1956-61

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ पर्यटन सुविधाओं के विकास पर योजना बद्ध तरीके से काम शुरू हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना में, प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रहने और यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया । पर्यटन योजना को तीन भागों में विभाजित किया गया ।

भाग1:: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर आवास, यातायात और मनोरंजन की सुविधाएं विकसित करने पर ध्यान दिया गया । धन की व्यवस्था प्रबंधन और नियमन केन्द्र सरकार खुद करती थी । निर्माण सम्बन्धी सभी कार्य केन्द्र सरकार की संस्था पीडब्लूडी के माध्यम से होता था । इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर टूरिस्ट बंग्लों (प्रथम

श्रेणी) का निर्माण हुआ । बाद में इन्हें ''भारत पर्यटन विकास संस्थान' को सौंप दिया गया, जिसका नाम बदलकर 'यात्री लाज' हो गया ।

भाग 2:: इस कार्यक्रम में घरेलू पर्यटन के विकास को शामिल किया गया जिसमें अंतराष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल भी शामिल थे। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम से संचालित किया जाता था जिसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग की होती थी। हांलांकि इसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित उपक्रम ही कहा जाता था। इस कार्यक्रम में, राज्य पर्यटन व्यूरों का भी प्रावधान किया गया था जिसका काम घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना होता था ।

भाग 3:: इस भाग के अंतर्गत स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के उन पर्यटन स्थलों को रखा गया जहां जाने वालों में स्थानीय नागरिको की संख्या सबसे ज्यादा होती थी। इन स्थलों के रख रखाव प्रबंधन और खर्च आदि की व्यवस्था का भार राज्य सरकारों और उसके लोक निर्माण विभाग पर होता था।

2.3.3 तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लागू होने के वक्त तक सरकार को यह समझ में आ गया था कि पर्यटन, देश की उन्नति और विकास का एक प्रमुख उपकरण है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के ढांचा गत विकास के लिए अपनाये गये

कार्यक्रमों को तीसरी पंचवर्षीय योजना और आगे के तीन वार्षिक योजनाओं---1966-67,1967-68 और 1968-69 में भी जारी रखा गया ।

बाहर के देशों से भारत में पर्यटन पर आने वालों की संख्या बढने लगी जो एक दसक में बढकर छ गुना हो गयी । केन्द्र सरकार बाहरी पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से अपने कार्यक्रम बनाती थी जबकि राज्य सरकारों का मुख्य फोकस घरेलू पर्यटकों पर होता था । इससे,जिन इलाकों में पर्यटन की सुविधाये बिलकुल ही नहीं थीं वहां भी पर्यटन सुविधायें पहुचना शुरू हो गयीं। बोधगया ,खजुराहो, भुवनेश्वर, कोणार्क, महाबलीपुरम, सांची, तिरुचिरपल्ली, कांचीपुरम, मदुरै और तमाम दूसरे स्थानों पर बाहरी पर्यटकों को रहने और आवागमन आदि की सुविधायें प्रदान की गयीं।

योजना अवधि में पर्यटन सुविधाओं के विकास को बढावा देने के लिए, एल के झा कमेटी या तदर्थ कमेटी का गठन किया गया था । झा कमेटी (1963) ने कहा कि भारत में सरकारी संस्थानों को पर्यटन उद्योग के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए । झा कमेटी की संस्तुति के आधार पर ,1965 में, तीन सरकारी उद्यमों की स्थापना की गयी।

- होटल कारपोरेशन आफ इंडिया
- इंडिया टूरिज्म ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लिमिटेड
- इंडिया टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड

2.3.4 वार्षिक योजनायें (1966-69)

वार्षिक योजनाओं(1966-69)में, कुल 6757 करोड का प्रावधान किया गया था जिसमें 7 करोड पर्यटन के लिए आबंटित था । वार्षिक योजनाओं की अवधि की सबसे बडी उपलब्धि थी,1966 में 'इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन' (आईटीडीसी) की स्थापना । यह कारपोरेशन ,'होटल कारपोरेशन आफ इंडिया' ,'इंडिया टूरिज्म ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिग' और 'इंडिया टूरिस्ट कारपोरेशन' को मिला कर बनाया गया था । इसके बाद 1967 में , नागरिक उडडयन और पर्यटन मंत्रालय का गठन किया गया जो पर्यटन के विकास की दिशा में दूसरा महत्व पूर्ण कदम था।

योरोपियन देशों को ध्यान में रखते हुए,1968 में एयर इंडिया के सहयोग से 'आपरेशन योरोप' अभियान चलाया गया । पर्यटन विभाग द्वारा, एक बार फिर 1968 में ही , पर्यटन के विकास में भारत की सांसकृतिक परंपराओं और स्मारकों के महत्व का आकलन करने के लिए 'यूनेस्को' के विशेषग्यों की सेवाये ली गयीं। पर्यटन विभाग द्वारा 1968-69 में ही 'पर्यटन प्रतिक्रिया के पैटर्न' और खर्च का 'सर्वे' कराया गया । कर्ज आदि की सहायता देकर नये होटलों के निर्माण तथा मौजूद होटलों के नवीनीकरण के उपायों पर विचार किया जाने लगा। यह सब सोचना जरूरी इसलिये हो गया था कि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ रही थी और होटल जरूरत से काफी कम थे ।

अपनी प्रगति की जांच करें-2

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के मद में धन अलग से आबंटित नहीं किया गया था। क्यों?

.....

.....

.....

2. पर्यटन विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों की चर्चा करें ।

.....

.....

.....

2.4 **चौथी पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनायें**

इस भाग में,चौथी से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत् पयर्यटन विकास के लिए उठाये गये महत्व पूर्ण कदमों का उल्लेख किया गया

2.4.1चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)

चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को विदेशी मुद्रा की कमाई और रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत माना गया । इस योजना में, पर्यटन को बढावा देने के लिए निम्न लिखित कदम उठाये गये जिससे पर्यटन के क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ ।

1. पर्यटन प्रचार साहित्य,फिल्म और फोटोग्राफी, सेवा और जनसंपर्क तथा मेलों और प्रदर्शनियों के अलावा, पर्यटन विभाग विदेशों में विज्ञापन आदि अन्य कार्यक्रमों के जरिये भी प्रचार कार्य करता रहा है। 'आपरेशन योरोप' के सफल अभियान के फलस्वरूप 1969 और बाद के वर्षो में योरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ जिससे उत्साहित होकर 1971 में इस अभियान को यूके,अमेरिका, और कनाडा, (और 1977 में आस्ट्रेलिया , पूर्वी ऐसिया और पश्चिमी एसिया) तक विस्तारित किया गया ।
2. दूसरी पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास परिषद (नेशानल डेवलपमेंट कौंसिल) द्वारा निरस्त कर दिया गया और एक नयी व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटको के लिए ढांचागत सुविधायें विकसित करने की योजना बनाने की सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय पर्यटन विभाग को दे दी गयी। घरेलू पर्यटन के ढांचागत सुविधाओं के विकास का जिम्मा राज्यों के पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया ।
3. अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का किराया कम कर दिया गया । इससे भारत आने वाले पर्यटकों का पैटर्न ही पूरी तरह बदल गया । बाहर के पर्यटकों का भारत में आवागमन बढ गया । बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या में हुए बदलाव से, पर्यटकों की नयी श्रेणी वजूद में आई। इस नयी श्रेणी के पर्यटकों को देश में लम्बे समय तक रूकने के लिए आकर्षित करने की नयी जरूरतें सामने आईं।

4. प्राइवेट सेक्टर में होटल बनाने और परिवहन चालकों को गाडियां खरीदने के लिए ऋण देने का प्रावधान किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप 'पर्यटन परिवहन फलीट' का निर्माण किया जा सके। पर्यटन केन्द्रों पर कुल 5500 कमरों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, होटल निर्माण में सहायता देने के लिए 'होटल डेवलपमेंट लोन स्कीम' जारी किया गया ।
5. 'भारतीय पर्यटन विकास निगम'(आईटीडी) के इस कार्यक्रम में,होटल ,मोटल,तथा पर्यटक कुटीर बनाने के अलावा, पर्यटक बंगलों के विस्तारीकरण, नवीकरण, तथा अंतराष्टीय हवाई अड़डों पर परिवहन केन्द्र और कर-मुक्त दुकानें खोलने का काम भी शामिल किया गया ।
6. इस योजना में शामिल एकीकृत 'प्रोजेक्ट' में जिन पांच प्रकल्पों को शामिल किय गया , वे इस प्रकार हैं - 'गुलमर्ग शीत कालीन खेल', कोवालम और गोवा के 'बीच' पर 'रिसोर्ट' विकसित करना, कुल्लू और मनाली सहित कई एक प्रमुख बौद्ध स्थलों का विकास ।

'चौथी पंचवर्षीय योजना' में शामिल ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रकल्प थे जिन्हें पूरा किये जाने से देश में पर्यटन उद्योग का बडे पैमाने पर विकास हुआ ।

2.4.2 पांचवीं पंचवर्षीय योजना(1974-1979)

चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन उद्योग का विकास होना जो शुरू हुआ वह पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहा । पिछली योजना-अवधि में शुरू किये गये, पंद्रह युवा होटलों तथा ग्यारह पर्यटक बंगलों के निर्माण का काम इस योजना

में ही पूरा किया गया। पर्यटन को पूर्ववत बढावा देते रहने के लिए,भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) द्वारा , पर्यटकों को ठहरने तथा यात्रा आदि के लिए परिवहन व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य सुविधायें देने का काम पहले की ही तरह चलता रहा। होटल निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को ऋण देने का जिम्मा औद्योगिक वित्त निगम को दे दिया गया ।

पर्यटन की दृष्टि से दस महत्वपूर्ण पुरातात्विक केन्द्रों के चयन और विकास के लिए 'केन्द्रीय समन्वय समिति' तथा इन केन्द्रों के विकास का 'मास्टर प्लान' तैयार करने के लिए 'आवास और निर्माण मंत्रालय' की ओर से 'टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन'(टीसीपीओ) का गठन किया गया । कुशीनगर और श्रावस्ती के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे गये इलाकों की सूक्ष्म स्तरीय योजनाएं बनाने तथा फतेपुर सीकरी और ब्रजभूमि के परिसरों का विस्तृत पुरातात्विक चित्र तैयार करने का काम 'नेशनल इंस्टीटयूट आफ डिजाइन अहमदाबाद ' को सौंपा गया ।

राष्टीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के प्रशासन में सुधार लाने तथा नये अभयारण्यों और पार्को के निर्माण का सुझाव देने के लिए 1969 में एक 'विशेषज्ञ समिति' का गठन किया गया । पिछली योजना में प्रस्तावित वन काजीरंगा ,सरिस्का ,गिर ,कान्हां,बांदीपुर, मुदुमलाइ,पेरियार और तदोबा अभयारण्यों को विकसित करने के लिए चुना गया । पिछली योजना में प्रस्तावित 'फारेस्ट लाजेज ' का निर्माण इस योजना में किया गया । बाघों तथा दूसरे वन्य जीवों का शिकार करने पर प्रतिबंध लगने के साथ ही वन्य पर्यटन 'फोटो सफारी हालीडे' पर्यटन में बदल गया ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में दो तरह के अध्ययन कराये गये । पहले का विषय था - "भारत में पर्यटन पर होने वाले खर्च और आय का अध्ययन "। इस अध्ययन का उद्‌देश्य राष्टीय आय में पर्यटन क्षेत्र के आर्थिक योगदान -- कुल रोजगार और सरकार को मिलने वाले टैक्स का आकलन करना था। यह अध्ययन 'नेशनल कौंसिल आफ अप्लायड एकोनामिक रिसर्च(एन सी ए ई आर)' नामक संस्था की ओर से किया गया था जबकि दूसरे का विषय था -"गुलमर्ग शीतकालीन खेल परियोजना" के लिए "यात्रियों के परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली" का अध्ययन । यह अध्ययन "यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स (यूएनडीपी) " ने किया था ।

2.4.3 छठी पंचवषीर्य योजना (1980-85)

भारतीय पर्यटन के इतिहास में छठी पंचवषीर्य योजना (1980-85) एक मील का पत्थर था । इस योजना अवधि के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण काम हुए।

- 1982 मे देश में सबसे पहले पर्यटन नीति तैयार की गयी जिसमें भारत में पर्यटन के विकास तथा उन्नयन के उद्‌देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट किया गया । पिछली यूनिट में आप पहले ही पढ चुके हैं।
- पर्य्रटन को लाभकारी क्षेत्र बनाने के लिए 'पर्यटन परिपथ' की अवधारणा विकसित की गयी ।

यात्रा परिपथ की परिभाषा इस प्रकार की गयी - '' पर्यटकों के यातायात को नियंत्रित करने के लिये पहले से ही निर्धारित रास्ता ।

पर्यटन के एकीकृत विकास के लिए, राज्य-सरकारों से सम्पर्क करके, प्रत्येक राज्य में दो या तीन परिपथ चिन्हित किये गये । अंतर्राष्टरीय और घरेलू पर्य्रटन को बढावा देने के लिए कुल 61 यात्रा परिपथों और 440 पर्यटन केन्द्रों का पता लगाया गया। कुछ चुनिंदा यात्रा परिपथों के आसपास विकसित हो रहे पर्यटन केन्दों के विकास की अवधारणा को आधार बनाकर पर्यटन के विकास की योजना बनाई गयी।

2.4.4 सातवीं पंचवर्षीय योजना -

देश में पर्यटन की अपरिमित संभावना की पहचान सबसे पहले सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गयी। 'नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल' ने प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि पर्यटन को उद्ययोग का दर्जा दे देना चाहिए । इसका मतलब था कि निर्यात उद्योगों को मिलने वाली छूट और प्रोत्साहन अब पर्यटन गतिविधियों को भी मिलने लगेगा । इसके बाद पंद्रह राज्यों और तीन केन्द्र शाशित राज्यों ने पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया जबकि चार राज्यों ने होटल व्यवसाय को उद्योग की मंजूरी दे दी। पर्यटन के विकास में निजी उपक्रमों की साझेदारी पर ज्यादा जोर दिया गया जब कि ढांचागत विकास सार्वजनिक क्षेत्र के जिम्मे रखा गया।

योजना का मुख्य जोर घरेलू पर्यटन को बढावा देने तथा बाहरी पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने पर केन्द्रित था । मनोरंजन तथा अवकाश यात्राओं, बर्फ-स्कीयिंग,जलक्रीडाओं, साहसिक खेलों और 'बीच' और पर्वतीय क्षेत्रों के रिसोर्ट और सांस्कृतिक महत्व के केन्द्रों पर पर खर्च के लिए बजट का प्रावधान करने पर खास जोर दिया गया था।

छठी पंचवर्षीय योजना की सबसे खास बात थी कि एकीकृत आधार पर पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य-योजना बनाने के लिए सन 1986 में एक 'राष्ट्रीय समिति' का गठन किया गया ।

इस समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं-

- पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।
- पर्यटन परिपथों और पर्यटन के गैर पारम्परिक क्षेत्रों जैसे ट्रेकिंग शीतकालीन खेलों वन्य पर्यटन,बीच रिसोर्ट पर्यटन आदि को विकसित करना और पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में नये क्षेत्रों की खोज करना ।
- पर्यटन उद्योग को ऋण देने के लिए पर्यटन वित्त निगम की स्थापना करना ।
- विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालयों को नये सिरे से सुव्यवस्थित तथा पर्यटन सेवा को आधुनिक और अद्यतन किया जाना चाहिए ।
- राष्टरीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना और आईटीडीसी की भूमिका को फिर से परिभाषित करना चाहिए ।

- "इण्डिया टूरिज्म सेवा " नाम से एक विशेषीकृत पर्यटन प्रबंधन कैडर तैयार करना चाहिए ।
- 1983 में स्थापित "भारतीय पर्यटन और यातायात प्रबंधन संस्थान (आई आई टी टी एम)" को शैक्षणिक विकास की एक सर्वोच्च संस्था के तौर पर प्रभावी तरीके से विकसित करना चाहिए ।
- पर्यटन तथा मनोरंजन के प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए और पर्यटन के विकास के लिए खोजे गये क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का आकलन करना चाहिए ।

अपनी प्रगति की जांच करें -3

1. किस पंचवर्षीय योजना में 'राष्टरीय पर्यटन नीति' लागू की गयी ?

.....

.....

2. यात्रा परिपथ से क्या समझते हैं ?

.....

.....

3. नेशनल कमिटी आन टूरिज्म 1986 की प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालें ।

.....

.....

2.5 आठवीं नवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनायें

इस भाग में आठवीं नवीं और दसवी पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन के विकास की प्रमुख पहल कदमियों की संक्षिप्त चर्चा की गयी है ।

2.5.1 **आठवी पंचवर्षीय योजना (1992-97)**

आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के ढांचागत विस्तार और विकास में निजी क्षेत्र के उपक्रमों की भागीदारी बढाने पर जोर दिया गया था । निजी क्षेत्र के उपक्रूमों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन दिये गये । आठवीं पंचवर्षीय योजना कम खर्च में अधिक उत्पादन और संसाधनों के कुशल उपयोग की रणनीति पर आधारित थी । पर्यटन के विकास के लिए मई 1992 में एक राष्टरीय कार्ययोजना लागू की गयी। राष्ट्रीय पर्यावरण और विरासतों का संरक्षण, रोजगार के अवसर विकसित करना, पर्र्यटन उत्पादों का सामाजिक आथिर्क आदि अन्य क्षेत्रों में उपयोग इस कार्य योजना के प्रमुख अंग थे । इन सब विषयों पर हम लोग पहले की यूनिट में चर्चा कर चुके है ।

जापान के " ओवर सीज एकोनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ ई सी एफ)" के सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट और अजन्ता एलोरा क्षेत्र के

विकास का काम किया गया। कई स्थानों पर पर्यटन संकुल की स्थापना के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्रों की सेवा दक्षता में सुधार तथा हवाई अड्डों की कार्य प्रणाली कों सुचारू बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया ।

2.5.2 नवीं पंचवर्षीय योजना (11997-2002)

नवीं पंचर्षीय योजना का नीतिगत लक्ष्य पर्यटन को एक ऐसी चीज बना देना था कि यहां के शांत सुरम्य और सुरक्षित वातावरण में आकर पर्यटक आनन्द का अनुभव कर सके। निजी और सार्वजनिक उपक्रमों के पारस्परिक सहयोग से चुनिन्दा पर्यटन केन्द्रो और परिपथों के विकास पर बल दिया गया । पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस योजना में विकास के लिए कुल 21 नये परिपथ और 12 पर्यटन स्थल चिन्हित किये गये । इन स्थानों पर पर्यटन के आवश्यक संसाधनों का निर्माण करने के लिए सम्बन्धित राज्यों को आर्थिक सहायता दी गयी । घरेलू और बाहरी पर्यटन के लिए जरूरी प्राथमिक संसाधनों , जैसे आवास ,यातायात और अन्य नागरिक सुविधायें बढाने पर बल दिया गया । इस प्लान में, पर्यटन का क्षेत्र विस्तार करते हुए ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन,पर्यावरणीय पर्यटन, देशी और प्राकृतिक स्वास्थ्य पर्यटन, विरासत पर्यटन और युवा और वरिष्ठ नागरिक पर्यटन आदि नामों से पर्यटन के नये नये 'पैकेज' तैयार किये गये ।

2.5.3 दसवीं पंचवषीर्य योजना (2002-2007)

दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की बेहतरीन क्षमता होने की पहचान की गयी । 36 लाख नौकरियों के सृजन तथा सामाजार्थिक क्षेत्रों की क्षमता

का विस्तार करने के लिए दुनिया के पर्यटन बाजार में अन्य देशों की तुलना में अपने देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया । सन 2002 में 'अतुल्य भारत' नाम से सफल प्रचार अभियान चलाया गया। 2002 में ही देश में 'राष्टरीय पर्यटन नीति' लागू की गयी ।

2.6 ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना

.

जैसा कि ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में दिखाया गया है, इस भाग में ,पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए उठाये गये कदमों पर चर्चा केन्द्रित होगी।

2.6.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की सोच यह थी कि पर्यटन क्षेत्र में विकास के रास्ते से उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने लायक सुविधायें विकसित की जायेंगी । इससे लोगों को शारीरिक रूप से क्षमतावान , मानसिक तौर पर स्वस्थ, सांस्कृति स्तर पर समृद्ध होने और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने का अवसर मिलेगा । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2007-2012 की अवधि में पर्र्यटन मंत्रालय की ओर से लागू किये गये कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

i. पर्यटन स्थलों और परिपथों का ढांचगत विकास करना ।

ii. बाहरी मुल्कों में प्रचार पर्यटन बाजार का विकास ।

iii. आई एच एम एस/ एफ सी आई / एन आई डब्लू एस / एन आई ए एस/ एन सी एच एम सी टी को सहायता तथा सेवा प्रदाताओं की सेवा क्षमता बढाना ।

iv. पर्यटन की उन्नति के लिए देश के भीतर प्रचार और प्रसार के कार्यक्रम आयोजित करना ।

v. आमदनी बढाने वाले बडे प्रकलपों की सहायता करना।

vi. आवास निर्माण के क्षेत्र को प्रोत्साति करना।

vii. भूमि बैंक तैयार करना ।

viii. केन्द्रीय एजेंसियों की मदद करना ।

ix. अगले वीस साल की परिप्रेक्ष्य योजना को ध्यान में रखकर बाजार का अनुसंधान ।

x. सूचना तकनीक और कम्प्यूटरीकरण ।

xi. दूसरे (बाहरी सहायक प्रकल्पों और आई आई एस एम के लिए भवन निर्माण)

सुरक्षित और सम्मान जनक'' पर्यटन के लिए पर्यटन मंत्रालय और हितधारकों द्वारा आचरण संहिता का अनुपालन ।

27सितम्बर 2010 में '' सुरक्षित और सम्मान जनक '' शीर्षक आचरण संहिता पर पर्यटन उद्योग के प्रमुख हितधारक-संगठनों तथा 100 से अधिक उद्योग-प्रतिनितिधयों का बाकायदा हस्ताक्षर लिया गया ।

''सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन'' एक निर्देशिका है। पर्यटन गतिविध को सम्मानजनक बनाना इसका उद्देश्य है । मर्यादापूर्ण, सम्मानजनक सुरक्षित और शोषण मुक्त वातावरण देकर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों, खास कर महिलाओं में पर्यटन के प्रति रूचि पैदा करने के लिए इसे तैयार किया गया है।

इसमें निम्नलिखित तीन मुख्य कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया था ।

(i) गंतव्य स्थलों और परिपथों के लिए पर्यटन उत्पादों का विकास करना -

केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक मात्र यही ऐसा कार्यक्रम है जो पर्यटन परिपथों और गंतव्य स्थलों के एकीकृत ढांचागत विकास के लिए उपलब्ध पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा विश्वस्तरीय नये उत्पाद पैदा करने पर केन्द्रित है । गंतव्य सथ्लों और परिपथों के लिए क्रमश: पांच करोड और आठ करोड जबकि बडे आकार वाले गंतव्यों और परिपथों पर खर्च के लिए क्रमश: पचीस और पचास करोड की राशि स्वीकृत की गयी थी । इस कार्यक्रम में 65 ग्रामीण पर्यटन प्रकलनो को भी शामिल किया गया था।

(ii) विदेशी प्रचार और बाजार-विकास सहयोग -

भारत को, विश्व में, पर्यटन का सर्व प्रिय गंतव्य स्थल बनाने के लिए जोरदार प्रचार और विपणन अभियान की शुरुआत की गयी । भारत के 'अतुल्य भारत' ब्राण्ड का दुनिया के सभी प्रतिष्ठित तथा नवोदित बाजारों में प्रचार किया गया । चीन फांस और स्पेन आदि देशों में सुदूर क्षेत्रों

तक पहुंच बनाने के लिए, वहां की स्थानीय भाषा में 'अतुल्य भारत' का प्रचार किया गया । वहां के नवोदित बाजारों में पर्यटन मंत्रालय के कार्यलयों की स्थापना का भी प्रयास किया गया । अप्रैल 2008 में भारत का 14वां विदेशी पर्यटन कार्यालय बीजिंग में स्थापित किया गया ।

(iii) आई एच एम / एफ सी आई / आई आई टी एम / एन आई डब्लू एस / एन आई ए एस / एन सी एच एम सी टी को केन्द्रीय सहायता तथा सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता-निर्माण -

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव संसाधनों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए सांस्थानिक ढांचों का सृजन और उन्नयन करना था। 'इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट' और 'फूड क्राफ़्ट इंस्टीटच्यूट' जैसे नये नये संस्थानों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। **'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण'** कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, सेवा की बुनियादी तकनीक, खाना बनाने की तकनीक, कूडा निस्तारण, शिष्टाचार और व्यवहार, पोषण का महत्व, ऊर्जा संरक्षण तकनीक , गाईड का प्रशिक्षण इत्यादि अनेक प्रकार की प्रशिक्षण सेवायें देने का काम शामिल था । इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक अल्पकालिक 'फ़लैगशिप प्रोग्राम' , 'हुनर से रोजगार तक ' जारी किया गया । बाद में इस कार्यक्रम को विस्तार देते हुए इसमें गृह व्यवस्था, उपयोगिता और बेकरी को भी शामिल कर लिया गया।

हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम

पर्यटन मंत्रालय की ओर से 2009-10 में,कमजोर आय वर्ग के अधिकतम 28 वर्ष के आठवीं पास लोगों को, खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ उत्पादन में रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए 'हुनर से रोजगार तक'(एच एस आर टी) नाम से एक विशेष कार्यक्रम जारी किया गया। यह कार्यक्रम कुछ चुनिंदा राज्यों द्वारा संचालित संस्थानों और स्टार होटलों में, पर्यटन मंत्रालय से अधिकृत संस्थानों जैसे 'आइ एच एम' और 'एफ सी आई' की ओर से प्रायोजित किया जाता है ।

2.6.2 बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-17)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन उद्योग के विकास रणनीति निम्न प्रकार थी -

1. पर्यटन विकास का एक प्रो-पुअर दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य था - पर्यटन से गरीबों को आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक लाभ पहुंचाना। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन उ़द्योग का विकास गरीबी कम करने में सहायक हो सकता है।
2. पर्र्यटन की संभावनाओं से भरे,ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों और राष्टीय स्तर के दूसरे आकर्षण के केन्द्रों का क्लसटर अथवा सर्किट आधारित पर्यटन विकास

3. सभी हितधारकों के बीच औपचारिक तथा अनौपचाकि सम्पर्क विकसित करना और पर्र्यटन विकास की रणनीतियों को लागू कराने के लिए हर तरह की सरकारों में परस्पर समन्वय सथापित कराना।
4. पर्र्यटन के प्रभावी विकास के लिए स्थानीय लोगों के नजरिये को तरजीह देना। स्थानी पंचायतों और अलग अलग समुदायों से बात करना ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कुछ प्रमुख कार्यक्रम और पहल कदमियां

- सन 2014 में ई वीसा स्कीम लागू किया गया ।
- राष्टीय आंदोलन की तरह, 2अक्तूबर 2014 को देशव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया । इस अभियान का उद्दंश्य था - स्वच्छ भारत का सपना साकार करना।
- दो बडे कार्यक्रम संचालित किये गये- स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन परिपथ का विकास करना।

  और 'प्रसाद'- तीर्थ यात्रा का कायाकल्प तथा आध्यात्मिक विरासत का संवर्धन ।
- देश में पर्यटन का ढांचागत विकास करने का अभियान संचालित करना ।
- भारत में 'चिकित्सा पर्यटन को बढावा देने तथा के लिए सन 2015 में " नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड" नामक एक 'अम्ब्रेला' संस्था का निर्माण ।

- भारत को साल के 365 दिनो का 'गंतव्यस्थल' बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में फैले पर्यटन के तमाम उत्पादों, जैसे कि क्रूइस, एडवेंचर ,चिकित्सा , कल्याण ,गोल्फ , पोलो, मीटिंगस प्रोत्साहन सभाओं, प्रदर्शनिओं (एमआईसीई) , ईको टूरिज्म , फिल्म टूरिज्म ,इत्यादि को चिन्हित करके फैलाने और प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल ।

- 'अतिथि सेवा' (हास्पिटलिटी सेक्टर) के क्षेत्र में 8लाख दस हजार कर्मचारियों की कमी पूरा करने के लिए हास्पिटलिटी शिक्षण के लिए आवश्यक ढांचागत विस्तार करके इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमेंट और फूड क्राफट इंस्टीच्यूटस की नयी शाखायें खोलना ।

- बारह अंतर्राष्टीय भाषाओं- हिन्दी ,अंग्रेजी ,अरबी ,फ्रेंच ,जर्मन ,इटैलियन , जापानी ,कोरियन ,चाइनीज ,पुर्तगाली ,रसियन ,और स्पेनिश- में 24*7 बहुभाषी टाल फ्री हेल्प लाईन शुरू किया गया । यह सेवा टालफ्री नम्बर 1800111363 या इसके संक्षिप्त कोड 1363 पर उपलब्ध है। इसतरह बहुभाषी हेल्प डेस्क मुहैयया करा कर 2017 में "अतुल्य भारत " **2·0** का शुभारंभ किया गया । इस अभियान के साथ दुनिया भर में पहले से चले आ रहे प्रचार के पुराने तरीके पीछे छूट गये और बाजार

निर्भर प्रचार प्रचार योजनाओं और अंतर्वस्तु रचना का युग आरम्भ हुआ ।

अपनी प्रगति की जांच करें 4 -

1. वे कौन सी गतिविधियां थी जिसपर आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया ।

.....

.....

2. ''हुनर से रोजगार तक'' कार्यक्रम क्या है ।

.....

.....

3. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन विकास के लिए उठाये गये कदमों पर प्रकाश डालें ।

.....

.....

2.7 समापन

भारत में आजादी के बाद, समाजार्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत की गयी । 1951 और 2017 के बीच कुल बारह पंचवषीर्य योजनायें लागू की गईं। योजनाओं के माध्यम से पर्यटन सम्बन्धी मसलों का समाधान किया गया । पहली पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उस समय पर्यटन की तुलना में दूसरी बहुत जरूरी समस्यायें थी जिन्हें प्राथमिकता के स्तर पर हल करना था । लेकिन बाद की योजनाओं में पर्यटन के सामाजिक और आर्थिक महत्व को समझा गया । बाद के वर्षो में सरकार ने कई तरह की नीतियां और प्रोजेक्ट बनाकर पर्यटन उद्योग को विकसित किया

2.8 कुंजी शब्द

पंचवर्षीय योजना - सरकार ने एक केन्द्रीकृत समन्वित प्रारूप तैयार किया, जिसमें हर योजना के लिए पांच साल का समय निर्धारित किया गया । इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है । ये प्लान 'प्लानिग कमीशन' द्वारा बनाये और कार्यान्वित किये जाते थे ।

यात्रा परिपथ- यातायात के समय पर्यटकों की निगरानी के उददेश्य से पहले से ही निर्धारित किये गये रास्तों को 'यात्रा परिपथ' कहा गया ।

पर्यटन के विकास में अंत:क्षेत्रीय समन्वय - इसका अभिप्राय यह है कि संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने लिए परिवहन, होटल, रेलवे आदि को पर्यटन विभाग के साथ सहयोग समन्वय स्थापित करना चाहिए ।

राष्टरीय पर्यटन नीति - किसी देश में पर्यटन के विकास के लिए वहां की सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश ।

गरीब समर्थक(प्रोपूअर)पर्यटन विकास - पर्यटन के विकास से आय मे हुई वृद्धि को गरीबों तक पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना कि पर्यटन के विकास को बढावा देकर गरीबी में कमी लाई जा सकती है।

आई आई टी टी एम- इंडियन इंस्टीच्यूट आफ ट्रवेल एण्ड मैनेज मेंट

एन आई डब्लू एस - नेशनल इंस्टीच्यूट आफ वाटर स्पोर्टस

एन सी एच एम सी टी - नेशनल कौंसिल आफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नालाजी

2.9 अभ्यास की प्रगति जांचने के लिए कुछ संकेत-

अपनी प्रगति की जांच करें 1

1. भाग 2.1 और 2.2 देख कर अपना उत्तर लिखें
2. उपभाग 2.2.1 का अवलोकन करें ।

अपनी प्रगति की जांच करें 2

1. उप भाग 2.3.1 देखें
2. उप भाग 2.3.2 देखें

अपनी प्रगति की जांच करें 3

1. छठी पंच वर्षीय योजना। भारत की प्रथम राष्ट्रीय पर्यटन नीति सन 1982 में लागू हुई।
2. (देखें उप भाग 2.4.3)

3. देखें भाग 2.4.4. नेशनल कमिटी आन टूरिज्म 1986 का संदर्भ लें

अपनी प्रगति की जांच करें 4

1. देखें उपभाग 2.5.1
2. देखें उपभाग 2.6.1
3. देखें उपभाग 2.6.2

2.10 फिरसे पढें

1. तिवारी एसपी, टूरिज्म डाइमेसन्स, आत्माराम एण्ड सन्स 1994
2. रिपोर्ट आफ वर्किंग ग्रुप आन टूरिज्म ,12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) http://164.100.158.43/sites/default/files/020220120146055.pdf
3. खान एमए,नूर एमए, खान एमए, टूरिज्म डेवलपमेंट इन इंडिया अनडर गवर्र्नमेंट फाइव ईयर प्लान्स,
4. फाजिल ए आई । असरफ एएच ,टूरिज्म इन इंडिया प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट,सरूप एण्ड सन्स 2006